उद्योगों की मांग अनुसार बनेगा मास्टर प्लान

औद्योगिक गलियारों का मामला

- **बड़े उद्योगों के साथ छोटी इकाइयों, ओडीओपी व वेयरहाउस की स्थापना पर होगा विशेष जोर**
- **औद्योगिक क्षेत्र के लिए 5769 हेक्टेयर भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू, 8000 करोड़ होंगे व्यय**

राब्यू, लखनऊ : प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाकर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही इनके किनारे बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक गलियारे बनाने की योजना अब कागज से जमीन पर उतरने लगी है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा विकसित किए जा रहे औद्योगिक गलियारों के लिए जिलों में भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करीब आठ हजार करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के 29 जिलों में 5769 हेक्टेयर भूमि खरीदी जाएगी। इसके साथ ही मास्टर प्लान पर भी अमल की तैयारी है। इसे उद्यमियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी मांग के अनुसार बनाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि बड़े उद्योगों और छोटी इकाइयों के साथ-साथ ओडीओपी उत्पादों को भी बढ़ावा मिल सके। भंडारण की समस्या के स्थायी निदान के लिए 30-40 प्रतिशत भूमि वेयर हाउस के लिए आरक्षित किए जाने की योजना है।

यूपीडा के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरि प्रताप शाही ने बताया कि भूमि क्रय के लिए संबंधित जिलों में करीब 1500 करोड़ की राशि भेज दी गई है। जमीन खरीदने के साथ ही औद्योगिक गलियारों के विकास का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार की कोशिश होगी कि उद्योगों को उनकी मांग के अनुसार उचित कीमत पर जमीन मुहैया हो सके।

एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे 30 औद्योगिक गलियारे : यूपीडा ने प्रदेश के 29 जिलों में पांच एक्सप्रेसवेज के किनारे औद्योगिक गलियारों की स्थापना की दिशा में प्रयास तेज किए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 11 औद्योगिक गलियारों के लिए 1522.05 हेक्टेयर भूमि क्रय की जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे छह गलियारों के लिए 1884.11 हेक्टेयर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे छह गलियारों के लिए 1585.57, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे पांच औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 532.28 हेक्टेयर व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे दो औद्योगिक गलियारे विकसित करने के लिए 245.35 हेक्टेयर भूमि क्रय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए 29 जिलों में 108 गांव अधिसूचित किए गए थे। गोरखपुर में सिर्फ बहादुरपुर बुजुर्ग व बहादुरपुर खुर्द से ही आवश्यक भूमि की व्यवस्था होने से अन्य गांवों में भूमि क्रय के प्रस्ताव को टाल दिया गया है, इसलिए अब चिह्नित गांवों की संख्या घटकर 102 हो गई है।

गलियारे के लिए किस जिले में कितनी जमीन की जा रही क्रय

गंगा एक्सप्रेसवे: मेरठ (212.2693 हे.), हापुड़ (111.0279 हे.), अमरोहा (139.377 हे.), संभल (168.773 हे.), बदायूं (132.050 हे.), शाहजहांपुर (109.287 हे.), हरदोई (128.911 हे.), उन्नाव (156.254 हे.), रायबरेली (100 हे.), प्रतापगढ़ (164.323 हे.), प्रयागराज (100 हे.)।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे : चित्रकूट (202.0640 हे.), बांदा (677.00 हे.), हमीरपुर (100 हे.), महोबा (100 हे.), जालौन (677 हे.), औरैया (110.047 हे.)।

लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे : आगरा (120 हे.), फिरोजाबाद (102.2580 हे.), इटावा (110.02 हे.), कन्नौज (100 हे.), कानपुर नगर (100.2693 हेक्टेयर)।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे : लखनऊ (90 हे.), बाराबंकी (243 हे.), अमेठी (100 हे.), सुलतानपुर (343 हे.), गाजीपुर (427 हे.), आंबेडकरनगर (382.57 हे.)

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे: गोरखपुर (100हे.),आंबेडकनगर(145.3582 हेक्टेयर)।